

सरकारी घाटे :(i) राजस्व घाटा - (Revenue Deficit)

राजस्व खर्च - राजस्व प्राप्तियाँ

$$₹ 200 - ₹ 100 = ₹ 100$$

$$₹ 200 - ₹ 300 = -₹ 100$$

(ii) प्रभावी राजस्व घाटा (Effective Revenue Deficit)

राजस्व घाटा - केन्द्र द्वारा राज्यों को पूँजीगत अनुदान (Capital Grants)

समृद्धि निर्माण की वार्त पर
दिए जाने वाले अनुदान।(iii) राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)

कुल खर्च (राजस्व + पूँजीगत)

(—)

राजस्व प्राप्तियाँ + NDCR



Non Debt Capital Receipts

Disinvestment विनिवेश

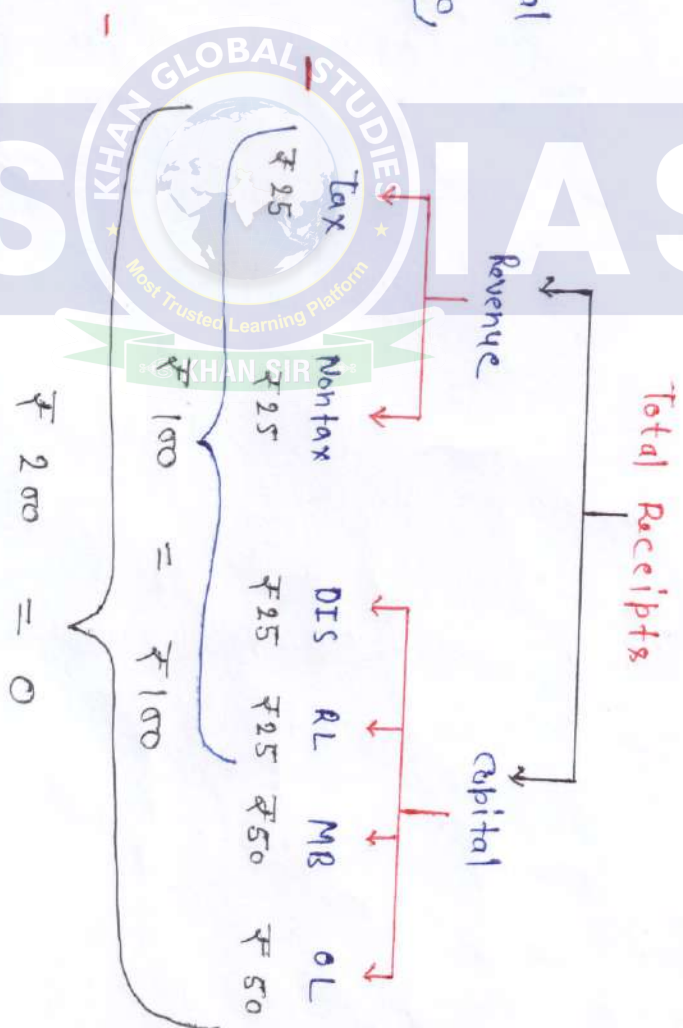
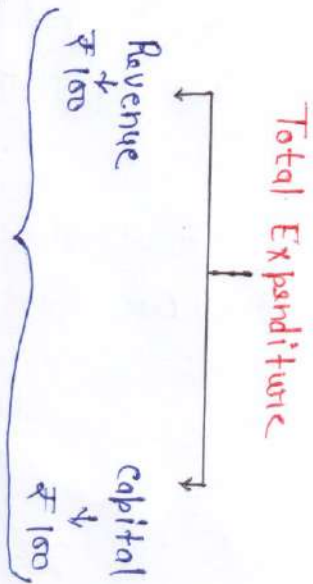
and

Recovery of Loans ऋणों की वसूली

Example :-

1. B.D. $\rightarrow$ ₹ 200

1. F.D. $\rightarrow$ ₹ 200



मह ध्यान देने योग्य हैं कि राजकोषीय घाटा सरकार की उधार आवश्यकताओं को प्रदर्शित करता है हालाँकि OL के कारण वास्तविक रूप में कम उधार ले सकती हैं।

भारत में सुखमोय चक्रवर्ती की सिफारिशों पर राजकोषीय घाटे की अवधारणा को लागू किया गया है।



इसके लागू होने से सरकार की वजतीय प्रक्रिया में पारदर्शिता उत्पन्न हुई है।

राजकोषीय घाटे से सरकार की राजकोषीय स्थिति का वास्तविक रूप में पता लग पाता है।

राजकोषीय घाटे से पहले बजट घाटे की अवधारणा का प्रयोग होता था इससे सरकार की वास्तविक राजकोषीय स्थिति का पता नहीं लग पाता था।

(iv)

बजट घाटा (Budget Deficit)



कुल खर्च - कुल प्राप्तियाँ



MB और OL को सम्मिलित करते हुए।

बजट घाटे को मोनेटाइज्ड घाटा (Monetised Deficit)

भी कहते हैं इसका कारण यह है कि यदि इस घाटे की मूल्य सकारात्मक होती है तो उसके बराबर भर्ष अवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है इसका कारण यह होता है कि इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को या तो केन्द्रीय बैंक से उधार लेना पड़ता है या केन्द्रीय बैंक के पास पड़े नगद शेष (Cash Balance) को निकलना पड़ता है। दोनों ही मामलों में मुद्रा की मात्रा का स्तर अर्थव्यवस्था

मे बढ़ जायेगा।

* Minimum Reserve System

₹ 100 करोड़ का कोष
न्यूनतम रखना होता है।

कुछ लोगो के अनुसार आर्थिक विकास के लिए भारत
जैसे राष्ट्र बजट घाटे का प्रयोग कर सकते हैं।
इस प्रकार की राजकोषीय नीति काफी खतरनाक
हो सकती है क्योंकि इसके कारण संबंधित राष्ट्र

Too much money chasing too few goods की
स्थिति में जा सकता है इस स्थिति में मुद्रास्फीति
तेज गति से बढ़ने लगती है।

Note:-

वर्तमान में भारत में बजट घाटे को शून्य
पर रखने की नीति का अनुकरण किया जा
रहा है।

∴ इस प्रकार, भारत में घाटे का (Monetisation)
मोड्रिकरण नहीं होता है

(v) प्राथमिक घाटा (Primary Deficit) :-

५

राजकोषीय घाटा - व्यय-भुगतान

F R B M Act $\Rightarrow$ Fiscal Responsibility and Budget - Management.

- (i) पारित - 2003
- (ii) लागू - जुलाई 2004
- (iii) आधारित - Gramm Rudman Hollings Act USA जो Balanced Budget पर जोर देता है।
- (iv) मुख्य लक्ष्य - (i) 2008-09 के अन्त तक राजस्व घाटे को शून्य करना।
(ii) 2008-9 के अन्त तक F. D को जी.डी.पी. (GDP) के 3% स्तर तक लाना
- (v) उपलब्धि - लक्ष्य प्राप्त नहीं की जा सकी क्योंकि भारत सरकार द्वारा 2007-9 की अमेरिकन मंदी से भारतीय अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए एक बड़ा Fiscal Stimulus लागू किया गया था।
- (vi) आलोचना :- शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि से जुड़े सामाजिक काम कम हो जाएंगे यह सौंच कर आलोचना हुई।
(UPSC Mains)